The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2019 (भाद्रपद 30, 1941) सं. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2019 (BHADRA 30, 1941) No. 38]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

	विषय	–सूची	
	पृष्ठ सं.		ष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक	*
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		आदेश और अधिसूचनाएं	-1-
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों	
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	483	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		प्राधिकरणीं (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक	
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,		नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य	
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में		स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी	
अधिसूचनाएं	1105	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत	
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों		के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित	
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में		होते हैं)	*
अधिसूचनाएं	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक	
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी		नियम और आदेश	*
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और	
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	2349	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल	
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध	
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों		और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई	
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	अधिसूचनाएं	4133
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियो		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और	
के बिल तथा रिपोर्ट	*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन	
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों	
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन	
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और		और नोटिस शामिल हैं	345
उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1675
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों	
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		को दर्शाने वाला सम्पूरक	*
आंक्र हे पाप्त नहीं हा।	'	"	

(483)

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and	110.	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	483 1105	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
Part I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2349	Part III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4133
language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Committee on Bills	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	345
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		Individuals and Private Bodies Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	1675
(other than the Ministry of Defence) and		Deaths etc. both in English and Tillidi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितंबर 2019

संकल्प

विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(2)/2019-एसडी (I)—संकल्प सं. एससी-(I) 86-III दिनांक 31.01.1986 के द्वारा इस्पात एवं खान मंत्रालय ने इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद (एसएससी) का गठन किया गया था, जिसमें सरकार, लौह एवं इस्पात के उत्पादक और उपभोक्ता, आवास निर्माण और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जब भी नए माननीय इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करते हैं तो समय-समय पर इस्पात उपभोक्ता परिषद (एसएससी) का पुनर्गठन किया जाता है। इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्य छोटे उत्पादकों की समस्याओं को हल करने और घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश में लौह एवं इस्पात की मांग और आपूर्ति से संबंधित मृद्दों के समाधान में सरकार की सहायता करना और परामर्श देना है।

2. माननीय इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में इस्पात उपभोक्ता परिषद का प्नर्गठन निम्नान्सार किया गया है:

(क)

(क)	माननीय इस्पात मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	माननीय इस्पात राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
(ग)	इस्पात मंत्रालय के सचिव	सदस्य
(ঘ)	संयुक्त सचिव (प्रभारी इस्पात विकास विंग, इस्पात मंत्रालय)	सदस्य सचिव

(ख)

।. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का एक प्रतिनिधि जिसका स्तर संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो :

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
1.	रक्षा उत्पादन विभाग
2.	भारी उद्योग विभाग
3.	अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
4.	आवास और शहरी मामले मंत्रालय
5.	जल शक्ति मंत्रालय
6.	रेल मंत्रालय
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
8.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
9.	नौवहन मंत्रालय
10.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम
11.	कोयला मंत्रालय
12.	पूर्वीत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनिअर)*
13.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
14.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
15.	खान मंत्रालय
16.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
17.	विद्युत मंत्रालय
18.	नीति आयोग (इस्पात और खनन क्षेत्र)

- (*) यदि बैठक पूर्वोत्तर में आयोजित की जाती है ।
- II. निम्नलिखित इस्पात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रतिनिधि:
 - 1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)
 - 2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
 - 3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन एम डी सी)
 - 4. क्द्रेम्ख आयरन ऑर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)
 - 5. मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (मेकॉन)
 - 6. मैंग्नीज ऑर इंडिया लिमिटेड (मायल)
 - 7. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी)
 - 8. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)
 - 9. बर्ड ग्रुप ऑफ़ कंपनीज (बी जी सी)
 - 10. संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी)
- III. केंद्र सरकार के तहत निम्नलिखित स्वायत्त निकायों / संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय / संगठन / पीएसयू का नाम
1.	सीमा सड़क संगठन
2.	भारतीय मानक ब्यूरो
3.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
4.	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) इंडिया लिमिटेड
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)
6.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
7.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएफएल)
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
9.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
10.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
12.	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय / संगठन / पीएसयू का नाम
13.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)
14.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल)
15.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
16.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
17.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)
18.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
19.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)
20.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड
21.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)
22.	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)
23.	अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ)

IV. लौह और इस्पात के निम्नलिखित प्रमुख उत्पादकों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	संगठन
1.	एस्सार स्टील
2.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.
3.	जेएसडब्ल्यू स्टील
4.	टाटा स्टील
5.	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
6.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)
7.	वेदांत लिमिटेड (इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड)

V. निम्नलिखित उद्योग संघों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	संघ
1.	ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुवाहाटी
2.	ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज (एआईएआई), मुंबई
3.	ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेसेज एसोसिएशन (एआईआईएफए)
4.	ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमओ)
5.	ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन, गाजियाबाद
6.	ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन
7.	एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिनी ब्लास्ट फर्नेसेज, नई दिल्ली
8.	ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए)
9.	बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
10.	छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
11.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (इस्पात और रसद)
12.	इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया
13.	फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), नई दिल्ली
14.	इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, गुरुग्राम

क्र. सं.	संघ
15.	इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए), नई दिल्ली
16.	आयरन एंड स्टील स्क्रैप शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
17.	लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली
18.	मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलकाता
19.	पेलेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
20.	स्टील वायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
21.	द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
22.	दइंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन
23.	एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
24.	एसोसिएशन ऑफ कंसिल्टंग सिविल इंजीनियरिंग (इंडिया), बेंगलुरु
25.	कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
26.	कन्फेडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई)
27.	कंसिल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली
28.	कच्छ उद्योग संघों का परिसंघ (एफओकेआईए)
29.	फेरो क्रोम प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एफसीपीए)
30.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, दिल्ली
31.	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स
32.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल, कोलकाता
33.	इंडियन रोड्स कांग्रेस
34.	इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी)
35.	मेटल कंटेनर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
36.	शिप पुनर्चक्रण उद्योग संघ (भारत)
37.	सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम)
38.	स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएमए)
39.	स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
40.	द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
41.	द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, मुंबई

VI. निम्नलिखित स्टील उपभोक्ताओं में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	उपभोक्ता
1.	हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड
2.	जिंदल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
3.	जिंदल पाइप्स लि.
4.	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5.	शापूरजी पलोनजी ग्रुप
6.	स्किपर लि.
7.	सूर्या रोशनी लिमिटेड

VII. निम्नलिखित सरकारी भारतीय पोर्ट में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र.सं .	उपभोक्ता
1.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट
2.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट
3.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड)
4.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, मुंबई
5.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम (कच्छ)
6.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
7.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
8.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
9.	न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर
10.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
11.	पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
12.	वी ओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन
13.	विशाखापद्दनम पोर्ट ट्रस्ट

VIII. उस स्थान के आसपास के सभी पोर्ट का एक प्रतिनिधि जहां बैठक आयोजित की जाती है:

IX. निम्नलिखित निर्माण और अवसंरचना कंपनियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:

क्र. सं.	संघ
1.	अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड
3.	शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

X. विशेषज्ञ

- तकनीकी विशेषज्ञ
 - o श्री अश्विनी कुमार (पूर्व सीईओ राउरकेला स्टील प्लांट),
 - o श्री अरुण कुमार रथ (पूर्व सीईओ भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गाप्र स्टील प्लांट),
 - o प्रो इंद्रनील मन्ना (आईआईटी खड़गपुर)
 - o प्रो के नरसिम्हा (आईआईटी बॉम्बे)
 - o डॉ. बास् (आईआईएमटी, एनएमएल)
- आईआईटी के प्रतिनिधि जहां इस्पात मंत्रालय ने चेयर को प्रायोजित किया है
- व्यापार से जुड़े मामलों को देखने वाले अर्थशास्त्री
 - o श्री अभिजीत दास, अर्थशास्त्री, आईआईएफटी
- XI. राज्य सरकार के निम्नलिखिति विभागों के सचिव/ एक प्रतिनिधि जहां बैठक आयोजित की जाती है:
 - इस्पात
 - खान
 - उद्योग

- आवास एवं शहरी विकास
- ग्रामीण विकास
- विद्युत
- 3. यह परिषद तब तक जारी रहेगी जब तक कि अध्यक्ष इस्पात मंत्री के पद पर बने रहेंगे। इस इस्पात उपभोक्ता परिषद का आरंभिक कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष होगा जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से इसे बढ़ाया या कम न किया जाए। जब भी जरूरत होगी तब इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, नीति आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

रुचिका चौधरी गोविल संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2019

- सं. एफ. 10/26/2018-यू.3(ए)—जबिक, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।
- 2. और जबिक, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं. 9-12/2001-यू.3 द्वारा सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे, को "समविश्वविद्यालय संस्था" घोषित किया था, जिसमें निम्नलिखित तीन संस्थान शामिल हैं:—
 - (i) सिंबायोसिस समिति विधि कालेज;
 - (ii) सिंबायोसिस व्यवसाय प्रबंधन संस्थान; और
 - (iii) सिंबायोसिस कंप्यूटर अध्ययन और अन्संधान संस्थान।
- 3. और इसके अतिरिक्त जबिक, मंत्रालय ने दिनांक 10.11.2006 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.9-12/2006-यू.3(ए) के जिरए निम्नलिखित संस्थाओं को सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे के दायरे में शामिल करने की अनुमित दी थी:

i.	सिंबायोसिस प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केन्द्र;
ii.	सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संस्थान;
iii.	सिंबायोसिस दूरसंचार प्रबंधन संस्थान;
iv.	सिंबायोसिस प्रबंधन अध्ययन संस्थान;
V.	सिंबायोसिस जनसंचार संस्थान;
vi.	सिंबायोसिस प्रचालन प्रबंधन संस्थान;
vii.	सिंबायोसिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र;
viii.	सिंबायोसिस जिओ इनफॉर्मेटिक्स संस्थान;
ix.	सिंबायोसिस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान; और
X.	सिंबायोसिस डिजाइन संस्थान

- 4. और जबिक, मंत्रालय ने दिनांक 17.04.2008 की अधिसूचना सं. 10-6/2007-यू3(ए) द्वारा सम विश्वविद्यालय को बंगलौर में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की है। सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र का नाम बदलकर सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और तत्पश्चात सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने दिनांक 17 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 10/07/2018- यू 3(ए) और दिनांक 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 10/08/2018 यू3 (ए) के माध्यम से सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (सम-विश्व विद्यालय), पुणे को अपने ऑफ-कैंपस क्रमशः नोएडा और हैदराबाद में शुरू करने की अनुमित प्रदान की थी।
- 5. और इसके अतिरिक्त, जबिक सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (सम-विश्वविद्यालय), पुणे ने नागपुर, महाराष्ट्र में नया ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए दिनांक 20.02.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन को जांच और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया गया था। यूजीसी ने आवेदन की जांच की और कुछ शर्ते पूरी करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने हेत् सिफारिश की थी।
- 6. और जबिक, यूजीसी की सलाह पर इस मंत्रालय ने नागपुर में प्रस्तावित ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले कुछ शर्ते पूरी करने के लिए 5 अप्रैल, 2019 को सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था। इसके बाद, सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय पुणे ने पत्र में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यूजीसी ने सम-विश्वविद्यालय की अनुपालन रिपोर्ट की जांच की और सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (सम-विश्वविद्यालय), पुणे को नागपुर में ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमित देने की सिफारिश की थी।
- 7. अब, इसिलए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से नागपुर, महाराष्ट्र में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने के लिए सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (सम-विश्वविद्यालय), को अनुमति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:
 - सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (सम-विश्वविद्यालय), पुणे अर्थात सिंबायोसिस न्यास के प्रायोजक निकाय के संघटन में इस अधिसूचना के जारी होने से 90 दिनों की अविध के भीतर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:
 - (क) कि, न्यास की स्थापना विशेष रूप से केवल शैक्षिक कार्यकलापों को संचालित करने के लिए की गई है।
 - (ख) कि, खंड 5 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना के संदर्भ को समाप्त किया जाए और कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जाए।
 - ii. नागपुर कैंपस की यूजीसी द्वारा यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने से 5 वर्षों की अविध के बाद समीक्षा की जाएगी।
 - iii. मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में निर्धारित सभी शर्तें जारी रहेंगी और संस्थान द्वारा उनका अन्पालन किया जाएगा।
 - iv. नागपुर में ऑफ कैम्पस की सभी चल और अचल परिसंपित्तयों/संपित्तयों के साथ साथ प्रबंधन कानूनी रूप से सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र में निहित होगा और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हित में पंजीकृत होगा।
 - v. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय/या इसके ऑफ कैम्पस केन्द्र की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का विपथन नहीं किया जाएगा।
 - vi. नागपुर ऑफ कैम्पस केन्द्र के साथ-साथ सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र व्यावसायिक और लाभ कमाने की प्रकृति के किसी भी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा।
 - vii. नागपुर में ऑफ कैम्पस केन्द्र में प्रदान किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों के अन्रूप होंगे।
 - viii. नागपुर का ऑफ कैम्पस केन्द्र, विषय पर, समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी मानकों, दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा।
 - ix. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र अपने ऑफ कैम्पस केन्द्रों के साथ-साथ सभी संघटक इकाइयों में डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्संधान कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए उचित कदम उठाएगा।
 - x. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र और इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र विद्यार्थियों के दाखिले, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का अद्यतन, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए

- पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को प्रारंभ करना, आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों के निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से लागू करेगा और इसका अन्पालन करेगा।
- xi. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र, जब कभी आवश्यक हो, यूजीसी के अनुमोदन से समझौता जापन/नियमों को नवीकरण या संशोधित या उपांतरित करेगा।
- xii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र के समझौता ज्ञापन/नियम, विनियम, उपनियम में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अन्मोदित सभी संघटक केन्द्रों और ऑफ-कैम्पस केन्द्रों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- xiii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र समय-समय पर संशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 के अनुसार यूजीसी के निर्देशों का पालन करेगा।
- xiv. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र और इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क ढांचे का अन्पालन करेंगे।

वी. एल. वी. एस. एस. सुब्बा राव वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 16 September 2019

RESOLUTION

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council—regarding.

No. 5(2)/2019-SD(I)—Vide Resolution No. SC-1(1)/86-III dated 31st January, 1986, the then Ministry of Steel & Mines had constituted a Steel Consumers' Council (SCC) under the chairmanship of Minister for Steel & Mines consisting of representatives of the Government, Producers and Consumers of Iron and Steel, House Builders and related industries. The SCC is re-constituted from time to time, as and when the new Hon'ble Steel Minister assumes the charge of Minister of Steel. The functions of the SCC is to assist and advice the Government in addressing the issues of small producers and fulfilment of the needs of the domestic consumers' and redressal of issues related to demand and supply of iron and steel in the country.

2. The Steel Consumers' Council, under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Steel Shri Dharmendra Pradhan is reconstituted as under:—

(A)

(a)	Hon'ble Minister of Steel	Chairman
(b)	Hon'ble Minister of State for Steel	Vice Chairman
(c)	Secretary, Ministry of Steel	Member
(d)	Joint Secretary (In-charge Steel Development Wing, Ministry of Steel)	Member Secretary

(B)

I. One representative from different Ministries/Department not less than level of Joint Secretary:

S.No.	Name of the Ministry/Department
1.	Department of Defence Production
2.	Department of Heavy Industry
3.	Department of Space, Indian Space Research Organization
4.	Ministry of Housing and Urban Affairs
5.	Ministry of Jal Shakti
6.	Ministry of Railways
7.	Ministry of Road Transport & Highways
8.	Ministry of Rural Development
9.	Ministry of Shipping
10.	Ministry of Civil Aviation
11.	Ministry of Coal
12.	Ministry of Development of North Eastern Region (DONER)*
13.	Ministry of Human Resource Development
14.	Ministry of Micro, Small& Medium Enterprises
15.	Ministry of Mines
16.	Ministry of Petroleum and Natural Gas
17.	Ministry of Power
18.	Niti Aayog (Steel & Mining Domain)

- (*) If meeting is conducted in NE.
- II. Representatives from each of the following Steel CPSEs:
 - 1. Steel Authority of India Ltd. (SAIL)
 - 2. Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL)
 - 3. National Mineral Development Corporation Ltd. (NMDC)
 - 4. Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL)

- 5. Metallurgical & Engineering Consultants Limited (MECON)
- 6. Manganese Ore India Limited (MOIL)
- 7. Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC)
- 8. Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)
- 9. Bird Group of Companies (BCG)
- 10. Joint Plant Committee (JPC)

III. One representative from each of the following Autonomous Bodies/Organisations/PSUs under Central Government:

S.No.	Name of Autonomous Body/Organization/PSU
1.	Border Roads Organization
2.	Bureau of Indian Standards
3.	Central Public Works Department (CPWD)
4.	National Buildings Construction Corporation (NBCC) India, Ltd.
5.	National Highway Authority of India (NHAI)
6.	Airports Authority of India (AAI)
7.	Bharat Earth Movers Limited (BEML)
8.	Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
9.	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
10.	Defence Research and Development Organization (DRDO)
11.	Engineers India Limited (EIL)
12.	Food corporation of India (FCI)
13.	Gas authority of India Limited (GAIL)
14.	Heavy Engineering Corporation Limited (HECL)
15.	Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
16.	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
17.	Inland waterways Authority of India (IWAI)
18.	IRCON International Limited
19.	National Thermal Power Corporation Limited (NTPC)
20.	Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) Limited
21.	Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL)
22.	Rail Vikas Nigam Limited (RVNL)
23.	Research Designs and Standards Organisation (RDSO)

IV. One representative from each of the following major Producers of Iron and Steel:

S.No.	Organization
1.	Essar Steel
2.	Jindal Steel& Power Ltd.
3.	JSW Steel
4.	Tata Steel
5.	Jindal Stainless Limited
6.	Nilanchal Ispat Nigam Limited (NINL)
7.	Vedanta Limited (Electrosteel Steels Limited)

V. One representative from each of the following Industry Associations:

S.No.	Association
1.	All Assam Small Scale Industries Association, Guwahati
2.	All India Association of Industries (AIAI), Mumbai
3.	All India Induction Furnaces Association (AIIFA)
4.	All India Manufacturers' Organisation (AIMO)
5.	All India Metal Forging Association, Ghaziabad
6.	All India Steel Re-rollers Association
7.	Association of India Mini Blast Furnaces, New Delhi
8.	Automotive Component Manufactures Association of India (ACMA)
9.	Builders' Association of India, Mumbai
10.	Chhattisgarh Sponge Iron Manufactures Association
11.	Confederation of Indian Industry (CII) (Steel & Logistics)
12.	Engineering Exports Promotion Council of India
13.	Federation of India Chambers of Commerce & Industry (FICCI), New Delhi
14.	Indian Stainless Steel Development Association, Gurugram
15.	Indian Steel Association (ISA), New Delhi
16.	Iron & Steel Scarp Shipbreakers Association of India, Mumbai
17.	Laghu Udyog Bharti, New Delhi
18.	Merchant's Chamber of Commerce & Industry, Kolkata
19.	Pellet Manufacturers Association of India, New Delhi
20.	Steel Wire Manufactures Association of India, Kolkata
21.	The Federation of Association of Small Industries of India, New Delhi
22.	The Indian Ferro Alloy Producers' Association
23.	Alloy Steel Producers' Association of India
24.	Association of Consulting Civil Engineering (India), Bengaluru
25.	Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India
26.	Confederation of Real Estate Developers' Association of India (CREDAI)
27.	Consulting Engineers Association of India, Delhi
28.	Federation of Kutch Industries Association (FOKIA)
29.	Ferro Chrome Producers Association (FCPA)
30.	Indian Association of Structural Engineers, Delhi
31.	Indian Chamber of Commerce
32.	Indian Institute of Metals, Kolkata
33.	Indian Roads Congress
34.	Institute for Steel Development & Growth (INSDAG)
35.	Metal Containers Manufacturers' Association
36.	Ship Recycling Industries Association (India)
37.	Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
38.	Sponge Iron Manufacturers Association (SIMA)
39.	Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association
40.	The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
41.	The Indian Institute of Architects, Mumbai

VI. One representative from each of the following Steel consumers:

S.No.	Consumer
1.	Hi-Tech Pipes Ltd.
2.	Jindal Industries Pvt. Ltd.
3.	Jindal Pipes Ltd.
4.	Megha Engineering. & Infrastructure Limited
5.	Shapoorji Pallonji Group
6.	Skipper Ltd.
7.	Surya Roshni Ltd.

VII. One representative from each of the following Government Indian Ports:

S.No.	Consumer
1.	Chennai Port Trust
2.	Cochin Port Trust
3.	Kamarajar Port Limited (Erstwhile Ennore Port Limited)
4.	Jawaharlal Nehru Port Trust, Maharashtra, Mumbai
5.	Deendayal Port Trust, Gandhidham (Kutch)
6.	Kolkata Port Trust
7.	Mormugao Port Trust, Goa
8.	Mumbai Port Trust
9.	New Mangalore Port Trust, Mangalore
10.	Paradip Port Trust
11.	Port Management Board, Andaman & Nicobar Islands
12.	V. O. Chidambaranar Port Trust, Tutocorin
13.	Vishakhapatnam Port Trust

VIII. One representative from the local ports in the vicinity of the location where the meeting is held.

IX. One representative from each of the following Construction & Infrastructure Companies:

S.No.	Association
1.	Adani Infrastructures & Developers Pvt. Limited
2.	Larsen & Toubro Limited
3.	Shapoorji Pallonji & Co. Pvt. Ltd.

X. Experts

- Technical Experts
 - o Mr. Ashwini Kumar (Ex. CEO Rourkela Steel Plant),
 - o Mr. Arun Kumar Rath (Ex. CEO Bhilai Steel Plant, Durgapur Steel Plant),
 - o Prof. Indranil Manna (IIT Kharagpur)
 - o Prof. K Narsimha (IIT Bombay)
 - o Dr. Basu (IIMT, NML)
- Representatives from IITs where Ministry of Steel has sponsored Chairs
- Economists dealing with trade related matters
 - o Mr. Abhijit Das, Economist, IIFT

XI. Secretary/One representative of the following Departments of State Government, where the meeting is held:

- Steel
- Mines
- Industry
- Housing & Urban Development
- Rural Development
- Irrigation
- Power
- 3. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Resolution unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, NITI Aayog and the Comptroller and Auditor General of India and the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

RUCHIKA CHAUDHRY GOVIL

Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 22nd August 2019

- No. F.10/26/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.
- 2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-12/2001-U.3 dated 06.05.2002, on the advice of UGC, had declared Symbiosis International Education Centre, Pune as an Institution Deemed to be University, consisting of the following three institutions:
 - Symbiosis Society's Law College
 - ii. Symbiosis Institute of Business Management
 - iii. Symbiosis Institute of Computer Studies & Research
- 3. And further whereas, the Ministry vide its notification No.F.9-12/2006-U.3(A) dated 10.11.2006 permitted Symbiosis International Educational Centre, Pune for inclusion of the following Institutions under its ambit:
 - i. Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development;
 - ii. Symbiosis Institute of International Business;
 - iii. Symbiosis Institute of Telecom Management;
 - iv. Symbiosis Institute of Management Studies;
 - v. Symbiosis Institute of Mass Communication;
 - vi. Symbiosis Institute of Operations Management;
 - vii. Symbiosis Centre for Information Technology;
 - viii. Symbiosis Institute of Geo-Informatics;
 - ix. Symbiosis Institute of Health Sciences, and
 - x. Symbiosis Institute of Design

- 4. And whereas, the Ministry, vide Notification F.No.10-6/2007-U.3A dated 17.04.2008, permitted the Deemed to be University to start an Off-Campus Centre at Bengaluru. The name of Symbiosis International Education Centre has also been changed to Symbiosis International University and subsequently changed to Symbiosis International. Further, the Ministry, vide Notification No. 10/7/2018-U3(A) dated 17th August, 2018 and Notification No. 10/8/2018-U3(A) dated 20th August, 2018 permitted Symbiosis International (Deemed to be University), Pune to start its Off-Campus Centres at Noida & Hyderabad respectively.
- 5. And further whereas, Symbiosis International (Deemed to be University), Pune submitted an application on 20.02.2019 for establishment of new off-campus centre at Nagpur, Maharashtra. The same was forwarded to UGC for examination and advice. The UGC examined the application and recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) for fulfillment of certain conditions.
- 6. And whereas, on the advice of UGC, this Ministry issued Letter of Intent (LoI) to Symbiosis International, Pune on 5th April, 2019 for fulfillment of the certain conditions before starting of proposed Off-Campus Centre at Nagpur. Subsequently, Symbiosis International, Pune submitted the compliance report in respect of the conditions stipulated in LoI. The UGC verified the compliance report of the Deemed to be University and recommended for giving permission to Symbiosis International (Deemed to be University), Pune for starting of Off-Campus Centre at Nagpur.
- 7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Symbiosis International (Deemed to be University) to start an Off-Campus Centre at Nagpur, Maharashtra, with effect from the issuance of this Notification. This declaration is further subject to the following conditions:
 - i. The composition of Sponsoring Body of Symbiosis International (Deemed to be University), Pune i.e. Symbiosis Trust will be amended to the following effect within a period of 90 days from issuance of this Notification:
 - a) That, the Trust is established exclusively for running educational activities only.
 - b) That, reference to establish Private Limited Company in Clause 5 shall be deleted and substituted with reference to a company established under Section 8 of the Companies Act, 2018.
 - ii. The Nagpur Campus shall be reviewed by UGC after a period of five years from issuance of this Notification as per provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
 - iii. All conditions that were stipulated in the Ministry's earlier Notifications shall continue to be in force and shall be complied with by the Institution.
 - iv. The management as well as all the moveable and immovable assets/properties of the Off-Campus at Nagpur shall be legally vested with Symbiosis International, Pune, Maharashtra and registered as such in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education.
 - v. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus Centre(s), without prior permission of the UGC.
 - vi. Symbiosis International, Pune, Maharashtra as well as its Off-Campus Centre at Nagpur shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
 - vii. The academic programmes to be offered at the Off-Campus Centre at Nagpur shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.
 - viii. The Off-Campus Centre at Nagpur shall start new academic courses only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
 - ix. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units as well as its Off-Campus Centre(s).
 - x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre(s).
 - xi. As and when necessary, Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules with the approval of the UGC.
 - xii. The MoA/Rules, Regulations, Bye-laws of Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall clearly specify/reflect the names of all its constituent units and Off-Campus Centre(s), as are approved by the Central Government.

- xiii. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.
- xiv. Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO Senior Economic Advisor